

सच्चाई के दम पर
जोश के साथ...

सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया



महाराष्ट्र सरकार
ने इस्लामपुर का
नाम बदल
ईश्वरपुर किया

कानपुर, शनिवार, 19 जुलाई, 2025
वर्ष: 02, अंक: 194, पृष्ठ: 8+4

इनसाइड युवक ने कमिश्नर से लगाई न्याय की गुहार ... Pg03

Pg 12

यमुना एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा 6 की मौत, 2 घायल

पिता और दो बेटों के साथ सड़क पर बिखरी थीं लाशें, ऐसा दृश्य देख कांप उठे लोग

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मथुरा। यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह हुए भयानक हादसे में पिता और दो बेटों के साथ छह लोगों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। यह परिवार नोएडा में रहता है, जो भंडारा कराने के लिए अपने पैतृक गांव आ रहा था।

यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के बलदेव क्षेत्र में कार सवार कैटरिंग कारीगर के परिवार पर मौत ने झपट्टा मारा। अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कैटरिंग कारीगर के साथ उसके दो बेटे, दो भांजे और एक दोस्त की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। हादसा इतना भीषण था कि दो लोगों की लाश कार में फंस गई। पुलिस ने उनकी लाशों को बमुश्किल बाहर



निकाला। एक के बाद एक कर छह लाशों मार्ग पर रखी गईं।

कार में सवार बासौनी के हरलालपुरा गांव के रहने वाले धर्मवीर (48) समेत घर के दोनों चिराग बुझ गए। मृतकों में धर्मवीर के बड़पुत्रा हुसैद महोबा के दो भांजे दलवीर उर्फ छुल्ले, पारस सिंह, बेटे रोहित का दिल्ली का रहने वाला दोस्त

दुष्यंत शामिल है। मृतक की पत्नी सोनी, बेटी पायल अस्पताल में जिंदगी के लिए जूझ रही हैं। सभी अखंड रामायण पाठ और भंडारा करने के लिए दिल्ली से बटेश्वर के लिए निकले थे। मौत की सूचना मिलते ही गांव में मातम पसर गया है। परिवार के लोग मौके की ओर दौड़ पड़े हैं।

कैटरिंग का काम करता था धर्मवीर : हरलालपुरा निवासी धर्मवीर अपने परिवार के साथ दिल्ली के समयपुर बादली में रह कर कैटरिंग का काम करते थे। उनके चचेरे भाई प्रहलाद सिंह ने बताया कि बटेश्वर में अखंड रामायण पाठ और भंडारा करने के लिए धर्मवीर परिवार के साथ शुक्रवार देर रात निकले थे। उनके कहने पर बटेश्वर में धर्मशाला बुक कर दी थी। परिजनों ने बताया कि रात 3 बजे के करीब यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के बलदेव में अज्ञात वाहन से कार टकरा गई। उन्होंने बताया कि शनिवार तड़के 4 बजे बासौनी पुलिस ने हादसे की सूचना दी। जिस पर परिवार के लोग मथुरा की ओर दौड़ पड़े। क्षेत्राधिकारी संजीव कुमार राय और थाना प्रभारी रंजना सचान ने बताया इको गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। मृत लोगों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पंजाब में आप को झटका

अनमोल गगन मान
ने दिया इस्तीफा



चंडीगढ़। गायिका रहीं अनमोल गगन मान 2020 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थीं। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में खरड़ से जीत हासिल की थी। खरड़ की विधायक अनमोल गगन मान ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। मान ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मेरा दिल भारी है, लेकिन मैंने राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया है। विधायक पद से स्वीकर को दिया गया मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। मेरी शुभकामनाएं पार्टी के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि पंजाब सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। अनमोल गगन मान पंजाब सरकार में पर्यटन मंत्री रह चुकी हैं।

2022 विस चुनाव में जीतने वाली वह सबसे युवा नेताओं में से एक हैं। अनमोल गगन मान ने पार्टी का कैम्पेन गीत भी तैयार किया था।

शारदा यूनिवर्सिटी

मेरी मौत के लिए टीचर जिम्मेदार, डिप्रेशन में हूँ...

यहां ना सिक्वोरिटी
अच्छी ना खाना: छात्रा

21 साल की बीडीएस छात्रा ने लगाई फांसी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो/एजेंसी

ग्रेटर नोएडा। शारदा यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में शुक्रवार शाम बीडीएस सेकंड ईयर की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शनिवार सुबह यूनिवर्सिटी के बाहर परिजन और छात्र प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। स्थानीय लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। आरोप है कि शारदा यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से प्रताड़ित करने पर छात्रा ने सुसाइड किया है। छात्रा ज्योति शर्मा ने सुसाइड नोट में



लिखा है- 'अगर मेरी मौत हुई तो इसके लिए पीसीपी और डेंटल मेडिकल के टीचर जिम्मेदार होंगे। महेंद्र सर और शार्ग

मैम मेरी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। मैं चाहती हूँ कि वे जेल जाएं। उन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उन्होंने

मुझे अपमानित किया। मैं उनकी वजह से लंबे समय से डिप्रेशन में हूँ। मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी यही सब सहना पड़े। सॉरी... मैं अब और नहीं जी सकती।'

घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना नॉलेज पार्क पुलिस मौके पर पहुंची। गर्ल्स हॉस्टल मंडेला में 12वें फ्लोर पर कमरे में पंखे से लटका छात्रा का शव मिला। बीडीएस सेकंड ईयर की 21 वर्षीय ज्योति शर्मा गुरुग्राम की रहने वाली थीं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

एक छात्रा का कहना है कि ज्योति हमारी बैचमेट थीं। हम लोग खाना खा रहे थे तभी पता चला कि ज्योति ने सुसाइड कर लिया। वार्डन ने उसका सुसाइड नोट छिपा लिया था। शुक्रवार शाम को ज्योति हम लोगों से मिली थी। वह बहुत परेशान लग रही थी। अन्य छात्रों ने कहा कि 100 बच्चों पर एक फैकल्टी साइन लेने आती है। कुछ कमेंट कर दो तो तुरंत गेट आउट कर देते हैं। यहां न सिक्वोरिटी अच्छी और न ही खाना अच्छा है। शारदा यूनिवर्सिटी के पीआरओ अजीत कुमार ने कहा कि 2 टीचर को सस्पेंड किया गया है।

एक महीने बाद डीएम और सीएमओ आमने सामने

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में पंजीकरण, नवीनीकरण, स्थल परिवर्तन, चिकित्सक एवं मशीन जोड़े जाने से संबंधित प्राप्त प्रार्थना पत्रों का जिलाधिकारी द्वारा अवलोकन किया गया। डीएम ने सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी को निर्देशित किया कि पिछले 3 वर्षों में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत नियमों के उल्लंघन के मामलों में कितने चिकित्सा संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, इसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त प्रत्येक केंद्र में उन चिकित्सकों की सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाए, जिनके नाम पर

3 वर्षों में पीसीपीएनडीटी नियमों के उल्लंघन मामलों में रिपोर्ट प्रस्तुत करें सीएमओ



लाइसेंस निर्गत किया गया है।

70 दिन के अंदर समस्या का करें निस्तारण

जिलाधिकारी ने कहा कि अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदन का निस्तारण निर्धारित 70 दिवस की समय सीमा के भीतर किया जाए।

साथ ही, प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार को पीसीपीएनडीटी समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाए, जिसमें

लंबित प्रकरणों पर विचार किया जाए।

उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी चिकित्सा संस्थानों में दो बाई दो फीट आकार का एक स्पष्ट सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाए, जिस पर यह संदेश अंकित हो कि यहां लिंग निर्धारण नहीं किया जाता है। साथ ही, लिंग निर्धारण से संबंधित शिकायत के लिए निर्धारित हेल्पलाइन नंबर भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए।

विभिन्न आवेदनों में संस्तुति प्रदान की गई

नामित मजिस्ट्रेट व संबंधित चिकित्सकों की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रकरणवार विचार-विमर्श करते हुए विभिन्न आवेदनों में संस्तुति प्रदान की गई। कुछ प्रकरणों में नोटिस निर्गत किए जाने की कार्रवाई की गई।

8 लोगों के हुए नवीन पंजीकरण

बैठक में अस्पतालों से नवीन पंजीकरण के कुल 12 आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 8 को संस्तुति दी गई। नवीनीकरण के लिए प्राप्त 14 आवेदनों में से 11 को मंजूदी दी गई। 3 को नोटिस जारी की गई। स्थल परिवर्तन के 2 आवेदनों में से 1 को संस्तुत किया गया। चिकित्सक जोड़े जाने के लिए प्राप्त 2 आवेदनों को अनुमोदन प्रदान किया गया, जबकि मशीन जोड़े जाने के 6 में से सभी 6 आवेदनों को स्वीकृति दी गई। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी, सलाहकार समिति के सदस्य आर.के. सफफड़, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी सहित अन्य सम्मानित सदस्यगण उपस्थित रहे।

सिद्धनाथ घाट

घर से बिना बताए निकले थे, गोताखोर कर रहे तलाश

गंगा स्नान के लिए आए दो दोस्त डूबे

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। जाजमऊ के सिद्धनाथ घाट पर गंगा स्नान को गए चार दोस्तों में से दो गहराई में जाने से डूब गए। परिजनों और पुलिस को देर रात सूचना मिलने के बाद से गोताखोरों द्वारा उनकी तलाश जारी है।

कानपुर में जाजमऊ थानाक्षेत्र के सिद्धनाथ घाट में गंगा स्नान करने के लिए आए चार दोस्तों में दो दोस्त गहराई में जाने के कारण डूब गए। वहीं, साथ आए दो अन्य दोस्त डर गए।

उन्होंने घर जाकर देर रात परिजनों और पुलिस को जानकारी दी। गोताखोर लगातार किशोर की तलाश कर रहे हैं।

हालांकि अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल सका है।

नेताजी नगर पीएससी मोड़ निवासी सूरज, रौनक, राज और शुभम शुक्रवार देर शाम सभी सिद्धनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे।

इसके बाद सभी घाट के उस पार नहाने के लिए चले गए। सूरज और रौनक नहाने के लिए आगे निकल गए। राज और शुभम पीछे चल रहे थे। तभी अचानक अधिक गहराई में जाने से रौनक डूब गया।

किशोरों की तलाश कर रहे हैं गोताखोर

उस बचाने के चक्कर में सूरज भी डूब गया। इधर, हादसे के बाद देर शाम होने के चलते घाट पर सन्नटा पसरा हुआ था। थाना



घटना स्थल पर मौजूद पुलिस व ग्रामीण

प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि सुबह से ही गोताखोर किशोरों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि अभी उनका कुछ पता नहीं चल सका है। जल्द से जल्द

ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। घर से बिना बताए निकले थे सूरज यादव के पिता चंद्रपाल ने बताया कि चारों बिना बताए घर से ही निकले थे। सूरज पीएससी

मोड़ देख स्थित एक चाट की दुकान पर काम करता था। घटना के बाद से भाई निहाल, बहन सलोनी, मां गीता समेत परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है।

युवक ने कमिश्नर से लगाई न्याय की गुहार

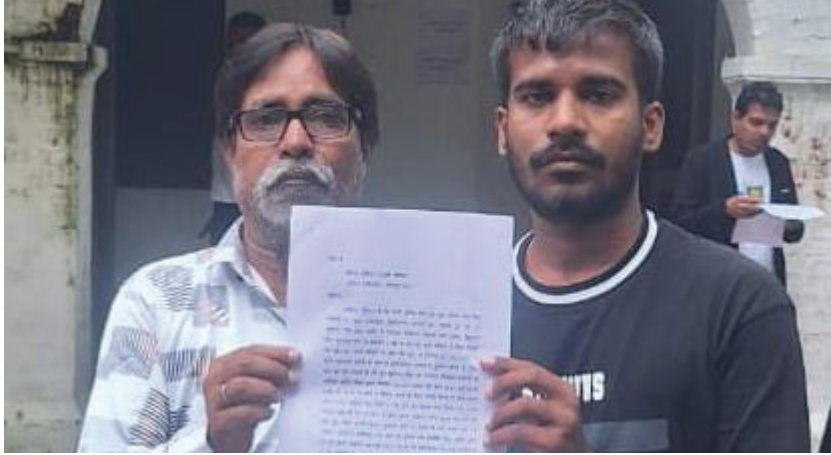
दबंग फर्म मालिक और कथित दलाल पर बंधक बनाकर धमकाने, मारपीट व जबरन चेक साइन कराने का आरोप

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो
कानपुर। शहर की प्रतिष्ठित दवा मार्केट बिरहाना रोड में कार्यरत एक पूर्व कर्मचारी द्वारा बंधक बनाए जाने, मारपीट और जबरन चेक साइन कराने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित सूर्यभान सिंह और उनके पिता अनिल सिंह, निवासी अवधपुरी, शुवलागंज (उन्नाव), ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई है।

अनिल सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनका पुत्र सूर्यभान सिंह पिछले चार वर्षों से नेशनल मेडिकल एजेंसी, बिरहाना रोड में काम सीखने के लिए नौकरी कर रहा था। काम सीखने के बाद 7 जुलाई 2025 को उन्होंने शुवलागंज, उन्नाव में बाबा महाकाल ट्रेडर्स नाम से अपनी खुद की दवा की दुकान शुरू की।

पीड़ित परिवार का आरोप है कि दुकान खुलने की जानकारी मिलते ही, नेशनल मेडिकल एजेंसी के मालिक अमित मिश्रा ने 16 जुलाई को सूर्यभान को सैलरी व हिस्सा के बहाने दुकान पर बुलाया, जहाँ उसे बंधक बना लिया गया।

पीड़ित के अनुसार, उसी शाम लगभग



आठ बजे उसके पिता अनिल सिंह को भी बेटे के फोन से फोन करके दुकान बुलाया गया। वहां पहले से मौजूद शिव कुमार गुप्ता, जो खुद को दवा मार्केट का महामंत्री और कलेक्टरगंज थाने का पुलिस मुखबिर बताता है, ने आते ही अभद्र गालियाँ देते हुए हमला कर दिया।

पीड़ित सूर्यभान का आरोप है कि शिव कुमार गुप्ता ने उनकी जेब से 7400 नगद छीन लिए और फर्म की चेकबुक से चेक संख्या 000005, 000007, 000008, 000009, 000010 पर जबरन हस्ताक्षर

करा लिए। यही नहीं, एक स्टांप पेपर पर भी जबरन दस्तखत करवाए गए। इसके साथ ही उनका Vivo Y200e मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। शिव कुमार ने धमकी दी कि यदि हर महीने 50,000 नकद नहीं दिए गए, तो उन्हें झूठे मुकदमों में फँसाकर जेल भेज दिया जाएगा। पीड़ित का यह भी कहना है कि अमित मिश्रा से अभी भी 70,000 की बकाया सैलरी मिलनी है, जिसे देने से उन्होंने इनकार कर दिया।

धमकी और डर का माहौल

पीड़ित परिवार ने बताया कि रात करीब

12 बजे उन्हें छोड़ा गया, लेकिन धमकी दी गई कि अगर पुलिस में शिकायत की, तो हत्या करवा दी जाएगी।

न्याय न मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी
पीड़ित सूर्यभान सिंह ने रोते हुए कहा कि यदि उसे जल्द न्याय नहीं मिला, तो वह आत्महत्या करने को मजबूर होगा। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी अमित मिश्रा, शिव कुमार गुप्ता व उनके साथियों की होगी।

इस पूरे प्रकरण में पीड़ित परिवार द्वारा कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई है। कार्यालय की ओर से कहा गया है कि मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आरोप पूरी तरह से निराधार है-

शिवकुमार गुप्ता

आरोपों को लेकर व्यापारी नेता शिवकुमार गुप्ता का कहना है कि मिश्रा जी की मार्केट में दुकान थी, उनकी तबियत खराब होने पर उक्त कर्मचारी ने दुकान में घालमेल कर लाखों का खेल किया, उसी को लेकर बातचीत हुई थी, पैसे ना देने पड़े इसके लिए आरोप लगाए जा रहे हैं।

307वां ऐतिहासिक महादंगल 21 जुलाई को जागेश्वर मंदिर में

» देश-विदेश के पहलवान दिखाएंगे दम

» महिला पहलवानों की भी होगी भागीदारी, नेपाल-बंगाल के नामी पहलवान होंगे

कटियार द्वारा किया जाएगा।

दंगल संयोजक जितेंद्र पांडे जीतू ने जानकारी देते हुए बताया कि यह ऐतिहासिक आयोजन लगातार 307 वर्षों से जारी है, और इस बार इसमें देश-विदेश से करीब 150 पहलवान हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि महिला पहलवान भी इस बार अखाड़े में पुरुष पहलवानों के साथ दो-दो हाथ करती नजर आएंगी। नेपाल से शंकर थापा और पारस थापा, वहीं पश्चिम बंगाल से चर्चित नकाबपोश पहलवान इस बार आकर्षण का केंद्र रहेंगे। नकाबपोश पहलवान की खासियत है कि वह पूरे मुकाबले के दौरान अपने चेहरे को ढके रखता है। महिला वर्ग में



शिवानी, ममता, रिया समेत कई नामी महिला पहलवान अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगी। आयोजकों ने बताया कि अखाड़े की मिट्टी को मुलायम और पारंपरिक बनाने के

लिए उसमें दूध, मट्ठा और हल्दी मिलाई जाएगी। प्रेस वार्ता में जी.एस. मिश्रा (अध्यक्ष), प्राण श्रीवास्तव (महामंत्री), मनु तिवारी, शिवम पांडे, सूरज पांडे, रामचंद्र और नीरज

गुप्ता भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि यह आयोजन कानपुर की पारंपरिक पहलवानी संस्कृति और शिवभक्ति की विरासत को जीवंत बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

स्वराज इंडिया संवाददाता
कानपुर। श्री जागेश्वर महादेव प्रबंधक सभा के तत्वावधान में इस वर्ष भी सावन के दूसरे सोमवार, 21 जुलाई को ऐतिहासिक 307वां महादंगल आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 2:30 बजे कल्याणपुर विधायक नीलिमा

एन एच-91 के किनारे खड़ा है 'खतरनाक शेड' कभी भी हो सकता है हादसा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर के नानामऊ तिराहे पर एन एच-91 के किनारे बना यात्री शेड अब पूरी तरह जज्जर और खतरनाक हो चुका है। तस्वीरों में इसकी हालत साफ देखी जा सकती है, छत में गहरी दरारें हैं, किनारे झड़ चुके हैं, खंभों में सीलन है और लोहे की सरिया तक बाहर निकल आई है। यह शेड कभी यात्रियों के लिए राहत देने वाला एक प्रतीकालय हुआ करता था, लेकिन अब यह ढांचा खतरे का संकेत बन चुका है। इसकी छत किसी भी समय गिर सकती है और इसके नीचे बैठे राहगीर किसी बड़ी दुघटना का शिकार हो सकते हैं।

गर्मी की दोपहर हो, बारिश का दिन या धूप-छांव का समय-राहगीरों और ग्रामीण यात्रियों को बस या टैपों के इंतजार में इसी ढांचे के नीचे बैठना पड़ता है। छांव की तलाश में लोग इस जर्जर ढांचे में पनाह लेते हैं, लेकिन उन्हें हर वक्त गिरती छत का डर सताता है।

व्यस्त हाईवे पर खतरनाक ढांचा, फिर भी चुप्पी: यह यात्री शेड नेशनल हाईवे- 91 के मुख्य मार्ग पर स्थित है, जिससे रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि इसी मार्ग से आते-जाते हैं। इसके बावजूद किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया।

मरम्मत की कोई योजना नहीं बनाई गई

लोगों का कहना है खतरे के साए में साधन का इंतजार करना पड़ता है। यह ढांचा वर्षों से वैसा ही खड़ा है। हर बारिश के मौसम में इसकी हालत और बिगड़ जाती है, लेकिन अब तक न कोई निरीक्षण हुआ, न मरम्मत की कोई योजना बनी।

अब उठने लगी हैं आवाजें

यात्रियों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक कोई वैकल्पिक या सुरक्षित व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक यह ढांचा लोगों के लिए न सिर्फ असुविधाजनक बल्कि जानलेवा बना रहेगा। आसपास के ग्रामीण इलाकों से आने-जाने वाले लोग दिनभर इस जगह पर रुकते हैं और जोखिम के साए में सप्तर की शुरुआत करते हैं। जिस पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है।

» वाहन के इंतजार में जर्जर यात्री शेड में बैठना पड़ता
» कई वर्षों बाद नहीं की गई मरम्मत, बिगड़ी स्थिति



नानामऊ तिराह पर हाईवे किनारे बना यह शेड हादसे को न्योता दे रहा है।



बिजली कटौती से परेशान सपाइयों ने एसडीओ को सौंपा जापन

» कहा-अधोषित कटौती से किसान और आमजन बेहाल जल्द हो समाधान

बिल्हौर। बिल्हौर व अरौल क्षेत्र में लगातार हो रही अधोषित बिजली कटौती के खिलाफ शुक्रवार को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सपा नेत्री रचना सिंह गौतम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बिजली आपूर्ति में सुधार की मांग को लेकर बिल्हौर एसडीओ दफ्तर पहुंच एसडीओ अमर नाथ को जापन सौंपा।

सपाइयों ने कहा कि बिजली की आंख मिचौली से किसानों की फसलें सूख रही हैं, जबकि भीषण गर्मी में रातभर जागने को मजबूर आमजन का जीवन भी अस्त-व्यस्त है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की स्थिति बेहद खराब है, जिसे जल्द सुधारना जरूरी है। इस दौरान लोकेश अवस्थी, शशिकांत, अंशुमान समेत कई सपाई मौजूद रहे।

उठाई आवाज

सपा ने ककवन कोठीपुरवा में की बैठक, भाजपा सरकार की नीतियों को बताया गरीबों संग छल

स्कूल बंदकर गरीबों से छीनी जा रही शिक्षा : विनय यादव

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के सरकार के फैसले के विरोध में शुक्रवार को ककवन ब्लॉक के ग्राम ककवन कोठीपुरवा में समाजवादी पार्टी ने विरोध बैठक आयोजित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सपा बिल्हौर विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार गरीब और वंचित तबके से शिक्षा का अधिकार छीनने का काम कर रही है। यह सीधे सीधे उनके साथ छल करना है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को बंद करना सामाजिक असमानता को बढ़ावा देने जैसा है। यह फैसला न केवल बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित करेगा, बल्कि युवाओं के रोजगार के अवसर भी खत्म करेगा। जहाँ



पहले से ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, ऐसे में स्कूल बंद करना उनके भविष्य के साथ अन्याय है, उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जरूरी है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात संतुलित हो और गांव-गांव स्कूल सुलभ हों। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की यह नीति शिक्षा के प्रति उसकी

उदासीनता और बाजारवादी सोच को दर्शाती है। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान मेवालाल गौतम, अनिरुद्ध पाल, रामबाबू पाल, अनुसुगा सविता, शीलू पाल, संतोष पाल, नरेश कश्यप, बबलू कश्यप, सदाब खान, अंकित चक्रवर्ती, गोरे लाल दोहरे, ललित कुशवाहा, सूरजाना दोहरे सहित कई ग्रामीणों ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया।



सम्पादकीय

भारत पश्चिम के दबाव का विरोध करे

रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के दावों में नाकाम रहने के बाद ट्रंप प्रशासन अपनी खिसियाट उन देशों पर दबाव बनाकर निकाल रहा है, जो रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। जिनमें भारत के साथ चीन व ब्राजील भी शामिल हैं। इसके लिये अमेरिका नाटो के दुरुपयोग से भी नहीं चूक रहा है। आखिर शेष विश्व के देशों के व्यापारिक मामलों में नाटो की दखल का क्या औचित्य है? नाटो महासचिव मार्क रूट्टे की रूसी तेल आयात संबंधी धमकी पर भारत द्वारा कराया जवाब दिया गया है। लेकिन इस घटनाक्रम ने एक बार फिर वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर पश्चिमी देशों के दोमुहपेन को ही बेनकाब किया है। दरअसल, अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान, रूट्टे ने भारत, चीन और ब्राजील को चेतावनी दी है कि वे रूस पर यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिये दबाव बनाएं, अन्यथा दंडात्मक व्यापार शुल्क का सामना करने के लिये तैयार रहें। निश्चित रूप से रूट्टे की यह टिप्पणी अमेरिका के रूसी प्रतिबंध अधिनियम, 2025 की दिशा में बढ़ते समर्थन के साथ मेल खाती है। यह एक विधेयक है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप और 171 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। यह वही विधेयक है, जो रूस के तेल, गैस, यूरेनियम या पेट्रोकेमिकल्स का व्यापार करने वाले देशों पर पांच सौ फीसदी तक शुल्क लगाने का प्रस्ताव पेश करता है। उल्लेखनीय है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिये पूरी तरह से आयातित तेल पर निर्भर करता है। देश अपने कच्चे तेल का 88 फीसदी आयात करता है। जिसके चलते ही भारत ने पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड के प्रति ही आगाह किया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सीनेटर लिंडसे ग्राहम को नई दिल्ली की चिंताओं से अवगत कराया है। साथ ही भारत की वैध ऊर्जा आवश्यकताओं और अपनी आर्थिक दिशा स्वयं निर्धारित करने के संप्रभु अधिकार पर जोर दिया है। निश्चित रूप से दुनिया के तटस्थ और

विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की दादागिरी का पुरजोर विरोध करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि फरवरी में रूसी तेल आयात में 14.5 फीसदी की गिरावट आने के बावजूद, मास्को भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। जिसने मुश्किल वक्त में अन्य देशों के पीछे हटने पर भी भारत को रियायती दर पर कच्चा तेल देने की पेशकश की थी। भारत द्वारा पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड अपनाने के विरोध करने का तार्किक आधार है। हकीकत यह है कि यूरोपीय देश अन्य देशों और अपरोक्ष माध्यमों से रूसी कच्चे तेल का आयात जारी रखे हुए हैं। लेकिन चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ के देशों पर ऐसा करने पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं। भारत तथा तुर्की में परिष्कृत रूसी तेल को यूरोपीय संघ को फिर से निर्यात किया जाना पश्चिमी देशों के खोखलेपन को ही उजागर करता है। भारत ने इस दोगली नीति के प्रति अपना मुखर विरोध दिल्ली यात्रा के दौरान नाटो महासचिव के सामने जता दिया था। भारत का स्पष्ट कहना है कि उसके निर्णय अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर लिए जाएंगे। जिसको लेकर वह किसी तरह का बाहरी दबाव स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अपने मंसूबों में विफल होने के बाद पश्चिमी देश चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध बंद करने के लिये रूस पर दबाव बनाने हेतु दुनिया के अन्य देश उसकी हां में हां मिलाएं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में भी रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने पर अमेरिका ने रूस से भारत के तेल खरीदने को लेकर प्रश्न उठाये थे। तब भी भारत ने उसे अहसास कराया था कि हम अपने आर्थिक प्राथमिकताओं के मद्देनजर ही अपने फैसले लेंगे।

ट्रंप की तेल कूटनीति में नाटो का दुरुपयोग

पुष्परंजन

वर्ष 1949 में वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर के साथ गठित, 'नाटो' उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 32 देशों का एक सुरक्षा गठबंधन है। नाटो का मूल लक्ष्य, राजनीतिक और सैन्य साधनों से मित्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता, और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नाटो के दो मुख्य अंग हैं- राजनयिक, और सैन्य। यदि राजनयिक प्रयास विफल हो जाते हैं, तो नाटो सैनिक कार्रवाई के लिए धमकाता है। नीदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके मार्क रूट्टे, ट्रंप के खास लोगों में माने जाते हैं। बुधवार को वाशिंगटन में नाटो महासचिव मार्क रूट्टे ने कहा, कि रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन करना चाहिए, और उन्हें बताना चाहिए कि यूक्रेन से शांति वार्ता के बारे में गंभीर होना होगा, वरना ब्राजील, भारत, और चीन पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। रूट्टे ने कहा, 'इन तीन देशों को मेरा मशविरा है कि यदि आप पेइचिंग में रहते हैं, या दिल्ली में, या आप ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, तो आपको इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि यह आपको बहुत प्रभावित कर सकता है।'



सिजदा करने वाला संगठन है। दिक्कत, ट्रंप के साथ है। इस महीने रूस ने कीव पर 10 घंटे तक लगातार हमले किए। इन हमलों के बाद, 14 जुलाई को ट्रंप बोले, 'मैं राष्ट्रपति पुतिन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अब अमेरिका यूक्रेन को आत्मरक्षा के लिए ज्यादा हथियार देगा।' मतलब, ट्रंप का 'मिशन पीस' हो गया फ़िरस इस पूरी कहानी का दूसरा पक्ष है, तेल व्यापार। भारत में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की 23 रिफ़ाइनरियां हैं। रूस में 30 बड़ी और मध्यम आकार की रिफ़ाइनरियां हैं, जबकि अमेरिका में 131 रिफ़ाइनरियां हैं। अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। उसके बाद ही सऊदी अरब, रूस, कनाडा, चीन, इराक, यूएई, ब्राजील, ईरान और कुवैत क्रमशः आते हैं। एनर्जी इन्फ़ॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (ईआईए) को आशंका है, कि अमेरिकी कच्चे तेल का उत्पादन 2026 के अंत तक उस उच्च स्तर से कम हो जाएगा, क्योंकि तेल उत्पादक प्रतिस्पर्धी कीमतों से खरीदारों को लुभाएंगे। तेल उद्योग पर नज़र रखने वाले विशेषज्ञ इसे रूस से आयात करने वाले देशों पर दबाव बनाकर पुतिन को मजबूर करने की रणनीति के रूप में देखते हैं। रूसी तेल पर कीमतों को लेकर कोई 'कैपिंग' नहीं है, मास्को के कच्चे तेल की कीमत उस स्तर से नीचे है, तो पश्चिमी मालवाहक और बीमाकर्ता रूसी तेल व्यापार में भाग नहीं ले सकते। यह, एक किस्म की गुंडई है। भारत और चीन, रूसी कच्चे तेल के शीर्ष आयातक हैं। भारत अपनी लगभग 88 प्रतिशत कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद, जब पश्चिमी देशों ने रूसी कच्चे तेल से दूरी बना ली, तो रूस ने इच्छुक खरीदारों को अपने तेल पर छूट देना शुरू कर दिया।

यह धमकाना ही तो है। इसे आप ज़रूरत नहीं, तो क्या कहेंगे? खुन्नस आपको पुतिन से है, उसे निकाल रहे हैं, उन देशों पर, जो रूस से तेल व्यापार कर रहे हैं। एक अक्तूबर, 2024 से मार्क रूट्टे नाटो के महासचिव हैं। चार साल की कार्यवाधि में मार्क रूट्टे ट्रंप की कठपुतली जैसा कार्य करेंगे, यह उनके बयानों से दिख रहा है। ब्रसेल्स के बाहरी इलाके में स्थित, एक विशाल परिसर में स्टील और कांच से बने नाटो मुख्यालय में सात वर्षों तक मेरा जाना रहा। रूट्टे अपने पूर्ववर्तियों की तरह व्हाइट हाउस के आगे वयों नतमस्तक हैं? उसकी वजह है, पैसा। मोबाइल थल सेना, वायु रक्षा, लंबी दूरी की हथियार प्रणालियों और सुरक्षा कवच 'परमाणु छतरी' के लिए नाटो, दशकों से अमेरिका पर निर्भर रहा है। 'सेक्टर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस' के वरिष्ठ फेलो और पूर्व शीर्ष नाटो अधिकारी, जनरल गॉर्डन बी. डेविस जूनियर (सेवानिवृत्त) कहते हैं, 'नाटो की परमाणु छतरी, और पूरा सैन्य सेटअप अमेरिकी पैसे के बिना काम कर ही नहीं सकता।' कहने के लिए नाटो 32 उत्तर अटलांटिक देशों का सुरक्षा गठबंधन है, दरअसल यह अमेरिका को

समाज के विश्वास व पीड़ित की आशा का कानून

नए अपराधिक क़ानूनों का क्रियान्वयन

डा.0 सुमित मिश्रा

धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र के नाम से विख्यात हरियाणा ने एक बार फिर देश की न्याय व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन का सूत्रपात किया है। भारतीय न्याय प्रणाली की जड़ें महाभारत और मौर्यकाल जैसी सभ्यताओं में गहराई तक जमी रखीं। जहां नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और न्याय की सर्वोच्चता सदैव अक्षुण्ण रही। इसी परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए, हरियाणा ने 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुए तीन नए अपराधिक क़ानूनों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम- के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृहमंत्री के नेतृत्व में यह

परिवर्तन केवल विधियों में संशोधन नहीं, बल्कि न्याय-प्रणाली को औपनिवेशिक सोच से मुक्त कर संस्कृति, संवेदना और समसामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का एक क्रांतिकारी कदम है।

दरअसल, इन नए क़ानूनों में भीड़ हिंसा, उन्नत तकनीकी अपराध तथा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा ने इन क़ानूनों को ज़मीनी स्तर पर लागू करने हेतु ठोस तैयारी की। राज्य के सभी जिलों में पुलिस अधिकारियों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जांच अधिकारियों को आधार प्रमाणीकरण, त्वरित दस्तावेज़ीकरण और

वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धतियों से सुसज्जित किया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 346 के अंतर्गत अब गंभीर अपराधों की सुनवाई प्रतिदिन करना अनिवार्य है। इससे न्याय प्रक्रिया में विलंब कम हुआ है। 'चिह्नित अपराध' योजना के अंतर्गत 1,683 जघन्य अपराधों की निगरानी उच्चतम स्तर पर हुई जिनमें फरीदाबाद, डबवाली और करनाल जैसे जिलों में दोषसिद्धि 95 प्रतिशत से भी अधिक रही है। हरियाणा ने न्याय प्रणाली में तकनीकी नवाचारों को भी पूर्णतः अपनाया है। वाहन चोरी जैसे मामलों में स्वतः प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण, आधार सत्यापित बयानों की रिकॉर्डिंग और मेडलीपर प्रणाली के माध्यम से चिकित्सा परीक्षण और शव परीक्षण की रिपोर्टिंग को समयबद्ध किया गया। इसके परिणामस्वरूप 90 प्रतिशत से

अधिक मामलों का निपटारा एक सप्ताह के भीतर हुआ। ट्रैकिया प्रणाली के माध्यम से फॉरेंसिक प्रमाणों की जांच और लेखा-जोखा पूरी तरह पारदर्शी और उत्तरदायी बना है। फरवरी 2025 में राज्य सरकार द्वारा लागू हरियाणा गवाह संरक्षण योजना के तहत गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उन्हें विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, और उन्हें खतरे के अनुसार विशेष सुरक्षा प्रदान की गई। महिलाओं-बच्चों के विरुद्ध अपराधों के त्वरित निपटारा हेतु गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में विशेष त्वरित न्यायालय कार्यरत हैं। चिह्नित अपराधों के तहत मामलों की निगरानी से दोषसिद्धि दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अप्रैल 2025 तक 1,764 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें दोषसिद्धि दर 77.15 प्रतिशत रही। वर्ष 2024 में जुलाई से दिसंबर तक

यह दर 89 प्रतिशत तक रही। उल्लेखनीय मामलों में शीघ्र निर्णय हुए हैं। यमुनानगर जिले में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में 140 दिनों में मृत्युदंड दिया गया। इसी प्रकार गुरुग्राम और पानीपत के मामलों में मात्र 2 से 3 महीनों में निर्णय हो गया। अब न्याय में देरी की परंपरा समाप्त हो रही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 के अंतर्गत अब ऐसे आरोपियों के विरुद्ध भी सुनवाई संभव है जो न्यायालय से अनुपस्थित हैं। हरियाणा में ऐसे 193 मामलों की पहचान की गई है, और चार मामलों में न्यायालयों ने अनुपस्थित आरोपियों के विरुद्ध निर्णय भी दिए हैं। हरियाणा ने विचाराधीन बंदियों की पेशी के लिए वीडियो कान्फ़ेरेंसिंग को भी अपनाया है।

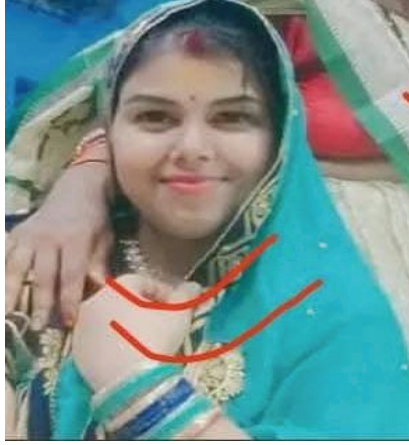


दहेज की खातिर गला दबाकर मार डाली बेटी, एक माह बाद भी आरोपी आज़ाद

» नवविवाहिता ने कई बार बताई थी प्रताड़ना की बात

» एफआईआर के बावजूद पुलिसिया ढिलाई, नहीं हुई अब तक गिरफ्तारी

प्रमुख संवाददाता दैनिक स्वराज इंडिया कानपुर नगर। चकेरी थाना क्षेत्र स्थित श्यामनगर केडीए कॉलोनी निवासी हिमांशु द्विवेदी ने 6 फरवरी 2023 को उन्नाव के नेहरू नगर निवासी अवधेश मिश्रा की पुत्री शिवांगी मिश्रा से विवाह किया था। विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष पति हिमांशु, सास मीरा देवी, ससुर अरुण द्विवेदी, जेट-जेटानी, मौसी सास और मौसरे जेट लगातार शिवांगी से एक पलैट और नकद रुपए की मांग



कर रहे थे। जबरदस्त मानसिक प्रताड़ना और मारपीट की शिकायतें शिवांगी ने कई बार अपने मायके पक्ष से कीं। एक 11 महीने के बेटे की मां

बन चुकी शिवांगी ने आखिरकार 23 जून को फोन पर कहा था ये लोग किसी दिन मुझे और मेरे बेटे को मार देंगे।

अगली ही रात शिवांगी की हालत बिगड़ने की सूचना परिजनों को दी गई। रीजेंसी से हैलट तक घुमाए जाने के बाद 29 जून को उसकी मौत हो गई। पिता अवधेश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि यह सुनियोजित हत्या है, जिसे आत्महत्या की शकल देने की कोशिश की गई।

मुकदमा दर्ज, पर गिरफ्तारी नहीं किसका दबाव है?

एफआईआर में दर्ज गंभीर धाराओं के बावजूद एक माह बाद भी किसी आरोपी की

गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि अस्पताल में इलाज में लापरवाही हुई और ससुरालियों के दबाव में प्रपत्र तक नहीं दिए गए। सवाल यह भी उठता है कि जब लड़की ने पहले ही प्रताड़ना की बात बताई थी और फोन पर धमकी जैसी बातें कहीं थीं, तो पुलिस ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया?

अब पूरा मामला प्रशासनिक ढिलाई और प्रभावशाली परिवार की पहुंच का प्रतीक बनता जा रहा है। शिवांगी की मौत के जिम्मेदार कब सलाखों के पीछे जाएंगे? और क्या 11 महीने का बच्चा अपनी मां के कातिलों को कभी सजा दिलवा पाएगा यह सवाल आज हर संवेदनशील नागरिक को झकझोर रहा है।

रोटरी क्लब ऑफ कानपुर क्लासिक का अधिष्ठापन समारोह संपन्न

आईएमए भवन, परेड में आयोजित किया गया कार्यक्रम

स्वराज इंडिया संवाददाता कानपुर। रोटरी क्लब ऑफ कानपुर क्लासिक का नव अधिष्ठापन समारोह मध्य रूप से आईएमए भवन, परेड में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद श्री देवेन्द्र सिंह भोले तथा सम्मानित अतिथि श्री अखिल कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस, कानपुर नगर, उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।

करते हुए क्लब द्वारा वर्ष भर किए गए सामाजिक कार्यों और अभियानों की रिपोर्ट साझा की। पूर्व सचिव रोटेरियन डॉ. देब ज्योति देबराय ने सचिव रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें वर्ष भर की गतिविधियों का विस्तार से उल्लेख किया गया।

इस अवसर पर रोटरी जिला गवर्नर रोटेरियन राजेन विद्यार्थी, आईएमए अध्यक्ष डॉ. नदिनी रस्तोगी तथा अन्य विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहे। स्थापना अधिकारी पी.डी.जी. रोटेरियन दिनेश शुक्ला ने नव निर्वाचित अध्यक्ष डॉ. देब ज्योति देबराय और उनकी कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। इसके साथ ही डॉ. अंजली सिंह ने एन विंग चेयरपर्सन के रूप



में शपथ ली। नव निर्वाचित अध्यक्ष डॉ. देब ज्योति देबराय ने अपने स्वीकृति भाषण में सेवा और समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

जिला गवर्नर रोटेरियन राजेन विद्यार्थी ने Unite for Good थीम पर आधारित कार्य करने की प्रेरणा दी और रोटरी के सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाने का

आह्वान किया। समारोह के अंत में नव सचिव रोटेरियन आलोक जैन ने सभी आगंतुकों, रोटेरियन सदस्यों तथा अन्य रोटरी क्लबों के पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। समारोह के संयोजक रोटेरियन संजय सिंह, आशीष गोयल, डॉ. राजीव केन्थ,

संजीव बंसल, ममता बंसल, मीनाक्षी सिंह, पूनम केन्थ एवं स्वीटी गोयल थे। मुख्य रूप से उपस्थित गणमान्य रोटेरियन्स में अनुज तुलसिआन, दिनेश चंद्र अग्रवाल, नरपत जैन, डॉ. अनुराग बंसल, मनीष जाखोदिया, गौरव नवेटिया, चार्टर अध्यक्ष डॉ. संजय सिंघवी आदि सम्मिलित रहे।

1025 लीटर अवैध डीजल के साथ पिकअप जब्त, आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा

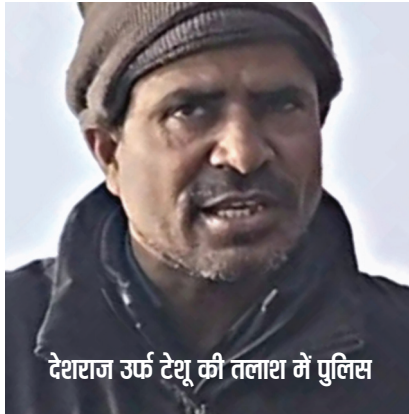
» मामा-भांजे की डील में निकला डीजल रैकेट

» पूर्ति विभाग और पुलिस ने मिलकर की बड़ी कार्रवाई

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर नगर। शिवराजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और पूर्ति विभाग की संयुक्त कार्रवाई से अवैध डीजल कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। बीते 16 जुलाई को दर्शनी पुलिस के पास चेकिंग के दौरान एक सदृश पिकअप वाहन (यूपी 77 T 4611) को रोका गया। पुलिस को वाहन की छत व बॉडी के भीतर कुल 25 पीपे मिले, जिनमें 1025 लीटर डीजल अवैध रूप से भरा था—जिसमें 5 बड़े पीपों में प्रति पीपा 65 लीटर व 20 अन्य पीपों में प्रति पीपा 35 लीटर डीजल भरा मिला।

वाहन चालक अमर सिंह, निवासी बैड़ी अलीपुर, ने बताया कि यह सारा डीजल उसके मामा देशराज निवासी रैपालपुर द्वारा उपलब्ध



देशराज उर्फ टेशू की तलाश में पुलिस

कराया गया था और दोनों इसे भौती क्षेत्र से भरवाकर बेचने की योजना बना रहे थे। पकड़े जाने के बाद देशराज मौके से फरार हो गया जबकि अमर सिंह को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। पूछताछ में सामने आया कि अमर सिंह के पास न तो किसी प्रकार का खरीद-विक्रय बिल था और न ही कोई परिवहन अनुमति।

डीजल तस्करी में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराएं लगाई गईं

पूर्ति निरीक्षक दिनेश कुमार वर्मा, क्षेत्रीय



खाद्य अधिकारी बिल्हौर, प्रभारी निरीक्षक शिवराजपुर व पुलिस टीम की उपस्थिति में थाना परिसर में गिनती कराई गई, जिसमें कुल 1025 लीटर डीजल की पुष्टि हुई। उक्त अवैध डीजल को यथास्थान पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया। इस संबंध में पूरी कार्रवाई की वीडियो ग्राफी भी कराई गई और रिपोर्ट जिलाधिकारी कानपुर नगर को सौंपी गई। जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरांत अमर सिंह व उसके मामा देशराज के विरुद्ध

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। बताया जा रहा है कि यह डीजल संभवतः ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचे दाम पर बेचा जाना था। देशराज की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और मामले की विस्तृत जांच पुलिस व पूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। यदि गैंग का नेटवर्क और बड़ा निकला तो केस गैंगस्टर एक्ट के तहत भी बढ़ाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक नीति, प्रोत्साहन एवं सब्सिडी पर आयोजित हुई कार्यशाला

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा अर्न्स्ट एंड यंग (EY) तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से शुरुवार को कानपुर में उत्तर प्रदेश औद्योगिक नीति, प्रोत्साहन एवं सब्सिडी योजनाएं विषय पर एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इस सत्र का उद्देश्य उद्यमियों, उद्योगपतियों एवं व्यवसाय से जुड़े लोगों को राज्य सरकार की नवीन औद्योगिक नीतियों, प्रोत्साहनों और सब्सिडी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देना और इन नीतियों के व्यावहारिक पहलुओं को समझाना था। कार्यशाला में कानपुर और



आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में उद्यमियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री

सुनील कुमार, संयुक्त आयुक्त, उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की MSME नीति पर विस्तार से चर्चा

करते हुए बताया कि राज्य सरकार किस प्रकार प्रक्रियाओं को सरल बनाकर लघु व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। श्री कुमार ने प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया और पात्रता, आवेदन प्रक्रिया तथा समयसीमा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा कीं।

कार्यक्रम में EY के वरिष्ठ प्रबंधक श्री निखिल पाधेय ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक नीति के अंतर्गत मिलने वाली प्रमुख सब्सिडी योजनाओं पर एक तकनीकी प्रस्तुति दी। उन्होंने पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, SGST प्रतिपूर्ति तथा लॉजिस्टिक्स अवसरचना सहायता जैसी

योजनाओं को विस्तार से समझाया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए दस्तावेजों की समयबद्ध तैयारी और योजना के अनुरूप कार्य करना अत्यंत आवश्यक है।

इस अवसर पर प्रतिभागियों को नीति विशेषज्ञों से प्रत्यक्ष संवाद का अवसर मिला, जिससे उनके संदेह दूर हुए और योजनाओं के लाभ उठाने की दिशा में मार्गदर्शन मिला।

कार्यशाला को प्रतिभागियों ने अत्यंत उपयोगी, व्यावहारिक और औद्योगिक दृष्टिकोण से समयानुकूल बताया।

राजपुर : बरसात बनी मुसीबत, कीचड़ से गुजरने को मजबूर लोहिया नगरवासी

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। राजपुर नगर पंचायत के लोहिया नगर मोहल्ले के निवासी इन दिनों भारी बारिश के चलते जलभराव की समस्या से परेशान हैं। मुगल रोड किनारे स्थित इस बस्ती में कच्चे रास्ते पर पानी भर जाने से आवागमन बेहद मुश्किल हो गया है। वार्ड के वाशिंगटन— अरशद अहमद, खुर्रम मंसूरी, सुर्जन सिंह, कामता प्रसाद, धर्मन्द्र गौतम, इदरीस, शिवम गुप्ता, रिशी आदि का कहना है कि शंकर के घर से तालाब तक का मुख्य रास्ता बारिश में कीचड़ और पानी से भर गया है। इससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन से

» कच्चे रास्ते में भरा पानी, पैदल चलना भी मुश्किल

» ईओ बोलीं— जल्द बनेगी आरसीसी सड़क

आरसीसी सड़क बनवाने की मांग की है। इस मुद्दे को वार्ड सभासद शमसाद अहमद ने भी गंभीरता से उठाया है और अधिशासी अधिकारी को पत्राचार कर तत्काल समाधान की मांग की है।

प्रशासन का भरोसा, होगा समाधान

राजपुर की अधिशासी अधिकारी नीति त्रिपाठी ने बताया कि उन्हें रास्ते की स्थिति की जानकारी है। जल्द ही जलभराव वाले



हिस्से में मिट्टी भराव और समतलीकरण निर्माण की कार्यवाही भी प्राथमिकता पर कराया जाएगा। साथ ही आरसीसी सड़क रहेगी, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

सड़क पर राख डालकर बहाया जा रहा 42 करोड़ का पसीना!

» नवीपुर-तिलौची फोरलेन सड़क में मिट्टी की जगह उड़ रही फैक्ट्रियों की राख

» मुख्यालय से महज़ 2 किलोमीटर दूर घटिया निर्माण, अफसर बने अनजान

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत कानपुर देहात के नवीपुर चौराहे से तिलौची रेलवे स्टेशन तक 3.5 किलोमीटर लंबे मार्ग का फोरलेन निर्माण 42 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है। यह मार्ग न केवल यूपीसीडा की 150 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को जोड़ता है, बल्कि हजारों गांवों के लाखों लोगों के लिए कचहरी, अस्पताल और आवागमन का मुख्य रास्ता भी है। लेकिन जिस क्वालिटी की उम्मीद थी, उसके नाम पर हो रहा है जमकर खेल।

स्थानीय लोगों और सूत्रों के मुताबिक, निर्माण में मिट्टी और कंक्रीट की जगह फैक्ट्रियों से निकली राख का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई स्थानों पर तो राख के ढेर खुले में पड़े हैं, जिससे सड़क की मजबूती पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आर.आर. एंटरप्राइजेज नामक ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता इस निर्माण की गुणवत्ता पर भारी पड़ रही है। क्षेत्रीय नागरिकों का आरोप है कि अधिकारियों की



मिलीभगत से घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, नहीं तो माती मुख्यालय और PWD दफ्तर के इतने पास हो रहे निर्माण में यह लापरवाही कैसे अनदेखी रह सकती है?

अफसरों ने माना, जांच के बाद कार्यवाही का भरोसा स्थानीय मीडिया द्वारा सवाल उठाए जाने पर लोक

निर्माण विभाग के अधिकारियों ने माना कि मिट्टी और कंक्रीट की जगह राख का प्रयोग गलत है और उन्होंने तत्काल जांच की बात कही है। विभाग का दावा है कि दोषी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह है कि जब यह सड़क आम जनता,

कारखानों और न्यायिक कामकाज का मुख्य मार्ग है, तो उसकी बुनियाद पर राख क्यों बिछाई जा रही है? क्या जिला प्रशासन और जिम्मेदार विभाग अब भी समय रहते जागेगे, या फिर सड़क बनने के कुछ ही महीनों में गड्डों से भरा एक और भ्रष्टाचार की मिसाल बनकर रह जाएगा?

ग्राम छतेनी में लगा वित्तीय जागरूकता का शिविर

» 100 से अधिक ग्रामीणों ने लिया योजनाओं में भाग, बीमा और पेंशन योजना पर मिला मार्गदर्शन

» 618 ग्राम पंचायतों में 30 सितंबर तक चलेंगे विशेष संतृप्ति शिविर

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक और एसएलबीसी के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष संतृप्ति अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत छतेनी में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा



योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, बैंक खातों में केवाईसी

अपडेट, नामांकन अद्यतन, और साइबर सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन और अग्रणी जिला प्रबंधक राकेश कुमार की निगरानी में आयोजित इस शिविर में लगभग 100 ग्रामीणों ने भाग लिया।

उन्होंने विभिन्न वित्तीय योजनाओं में रुचि दिखाई और मौके पर आवेदन भी किए। उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक जिले की 618 ग्राम पंचायतों में ऐसे शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को वित्तीय सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके गांव में मिल सके।

बिजली के साये में पढ़ाई, खतरे के बीच भविष्य गढ़ रहे बच्चे

» विद्यालय की छत से गुजर रही हाईटेंशन लाइन, जान जोखिम में

सूचना के बाद भी नहीं जागे जिम्मेदार अधिकारी



स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। परिषदीय विद्यालयों के भवनों पर और उनके पास से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइनें छात्रों और शिक्षकों के लिए खतरे का सबब बन चुकी हैं। कई स्कूल ऐसे हैं, जिनके ऊपर से 11 हजार वोल्ट की लाइनें गुजर रही हैं या परिसर में ट्रांसफार्मर लगे हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमरौली घर जैसे कई विद्यालयों में यह स्थिति वर्षों से बनी है, लेकिन अभी तक विद्युत विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। छात्र रोजाना जान हथेली पर रखकर पढ़ाई कर रहे हैं और शिक्षक भी भय के वातावरण में कार्यरत हैं।

हर रोज़ हदसे का डर, फिर भी चुप्पी

हालात इतने गंभीर हैं कि थोड़ी सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। शिक्षकों द्वारा कई बार विभागीय अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। बिजली की ये लाइनें और ट्रांसफार्मर सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से ही नहीं, बल्कि मानसिक दबाव के रूप में भी छात्रों पर असर डालते हैं। शिक्षकों ने एक बार फिर से मांग की है कि इन खतरनाक तारों को विद्यालय परिसर से तुरंत हटाया जाए, ताकि बच्चों को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा मिल सके।

24 लाख में बना मंडी भवन बना खंडहर

» न तो लगी मंडी, न हुआ इस्तेमाल नौ साल से खामोश पड़ा है विकास

» दुकानों में भी कारोबार की जगह चल रहे निजी धंधे

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। मलासा ब्लॉक के डीघ व गुरुगांव गांव में 2015 में मंडी समिति भवन और नीलामी चबूतरे का निर्माण हुआ था, जिसका उद्देश्य किसानों को एक स्थायी बाजार उपलब्ध कराना था। शासन से मिले 24 लाख रुपये की लागत से बनी इस मंडी में दो दुकानें और एक नीलामी चबूतरा भी तैयार किया गया। लेकिन बीते नौ वर्षों में यह भवन कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। यहां न तो किसी किसान की फसल बिकी और न ही कोई खरीदार आया। अब यह परिसर छुट्टा पशुओं, नशेड़ियों और बेघर मजदूरों की शरणस्थली बन चुका है। उपेक्षा की शिकार योजनाएं

स्थानीय स्तर पर इस मंडी समिति भवन को मामूली किराए पर



निजी लोगों को नीलाम कर दिया गया, लेकिन उन्होंने भी इसे अनाज और सब्जी बेचने की जगह दूसरे कार्यों में किराए पर देकर मुनाफा कमाने का अड्डा बना लिया। मंडी समिति का कोई संचालन नहीं हो पा रहा है और विकास की मंशा कागजों तक सीमित है। एडीओ सहकारिता सत्यम शिवहरे ने बताया कि मंडी के संचालन के लिए शासन को पत्र भेजा गया है, जल्द इसे क्रियाशील किया जाएगा। लेकिन स्थानीय लोगों में अब भरोसा नहीं बचा कि यह कभी वाकई मंडी बन पाएगी।

राजेंद्र नगर-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को पीएम ने दिखाई हरी झंडी

» गोविंदपुरी से विधायक मैथानी ने किया रवाना

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7200 करोड़ से अधिक की रेल, सड़क, मत्स्य, ग्रामीण विकास और आईटी परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसी अवसर पर चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई, जिनमें राजेंद्र नगर टर्मिनल (पटना) से नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन भी शामिल है।

गोविंदपुरी स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में गोविंद नगर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने ट्रेन को रवाना किया। कार्यक्रम की शुरुआत में अपर मंडल रेल प्रबंधक (इंफ्रा)

प्रयागराज नवीन प्रकाश ने अतिथियों को स्वागत करते हुए बताया कि गोविंदपुरी



और सूबेदारगंज पर ट्रेन के ठहराव से स्थानीय यात्रियों को लाभ मिलेगा।

यह पूरी तरह गैर-वातानुकूलित ट्रेन है, जिसमें 11 स्लीपर, 8 जनरल, 1 पैंट्री और 2 सीटिंग कम लगेज कोच हैं। विधायक मैथानी ने कहा कि इन ट्रेनों में बेहतर

इंटीरियर, एयर सिंगिंग सस्पेंशन, सीसीटीवी, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, 'कवच' सुरक्षा प्रणाली जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले और अब की रेलवे में बड़ा फर्क है, जो हर यात्री अनुभव कर रहा है।

कार्यक्रम में विधायक महेश त्रिवेदी, विधायक नीलिमा कटियार व जिला पंचायत अध्यक्ष स्वनिल वरुण भी मौजूद रहे। साथ ही, निबंध, चित्रकला व भाषण प्रतियोगिताओं के विजयी बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किए गए।

साहुकारों के तगादे से परेशान व्यापारी पांच दिन बाद परिवार सहित लौटा

» सुसाइड की थी योजना

» नहर में कूदने निकला था, लेकिन राहगीरों की समझाइश से बदला मन

स्वराज इंडिया संवाददाता

निंदूरा (बाराबंकी)। कुर्सी थाना क्षेत्र के बहरौली गांव से लापता हुआ तेल व्यापारी आजम शुक्रवार सुबह अपने पत्नी और पांच बच्चों के साथ थाने पहुंचा। व्यापारी ने पुलिस को बताया कि वह साहुकारों के दबाव और प्रताड़ना से तंग आकर परिवार सहित शारदा नहर में कूदकर जान देने के

इरादे से निकला था, लेकिन रास्ते में मिले दो अनजान व्यक्तियों ने उसे समझाया, जिससे उसका मन बदल गया और वह वापस लौट आया।

व्यापारी आजम ने बताया कि उसके ऊपर भारी कर्ज है और साहुकारों के लगातार तगादे, फोन कॉल्स और कारखाने पर आकर दबाव बनाने से वह मानसिक रूप से टूट चुका था। इसी कारण उसने 14 जुलाई की रात करीब 11 बजे पिकअप वाहन से अपने परिवार सहित घर छोड़ दिया।

व्यापारी परिवार ने गाड़ी में बिताए चार दिन

आजम ने बताया कि वह लगातार चार दिन तक गाड़ी चलाता रहा, और महमूदाबाद, सीतापुर होते हुए दिल्ली और गाजियाबाद तक पहुंच गया। इस दौरान परिवार के साथ उसने गाड़ी में ही रातें बिताईं, और होटलों व ढाबों पर

खाना खाया। वापसी में उसने सीतापुर में दो दिन रुककर शुक्रवार सुबह कुर्सी थाने में आत्मसमर्पण किया।

पुलिस ने की पुष्टि

कुर्सी थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि आजम की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पिता की तहरीर पर दर्ज की गई थी। शुक्रवार को आजम परिवार सहित सुरक्षित वापस लौट आया है। पूछताछ में उसने बताया कि साहुकारों से परेशान होकर उसने आत्महत्या की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में विचार बदल गया।

पांच दिन से लापता व्यापारी परिवार के सकुशल लौट आने से गांव में राहत की लहर है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि साहुकारों के उत्पीड़न की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि व्यापारी जैसे हालात दोबारा न बनें।

मल्लावां में विद्युत चैकिंग के दौरान कर्मचारी से अभद्रता से अभद्रता

» बिजली चोरी का मामला दर्ज, पूर्व में भी दर्ज हैं आरोपी पर बिजली चोरी के तीन मुकदमे

स्वराज इंडिया संवाददाता

निंदूरा (बाराबंकी)। फतेहपुर और बड़ड़पुर विद्युत उपकेंद्रों की संयुक्त टीम द्वारा शुक्रवार को ग्राम मल्लावां में की गई चैकिंग के दौरान सरकारी कर्मचारियों के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। चैकिंग टीम में शामिल एसडीओ ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि मल्लावां निवासी हसीब ने पोल से सीधे विद्युत तार जोड़कर एसी चला रखा था, जिससे करीब चार किलोवाट की बिजली चोरी की जा रही थी। जब टीम ने उसे रोकने और मूल्यांकन की कार्रवाई शुरू की, तो आरोपी ने न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग किया बल्कि अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन के कागजात भी फाड़ दिए। इसके साथ ही वह जांच में सहयोग करने से इनकार करता रहा। विद्युत विभाग ने आरोपी के खिलाफ बिजली चोरी और सरकारी कार्य में बाधा डालने व कर्मचारियों से दुर्व्यवहार की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी हसीब के खिलाफ पहले भी बिजली चोरी के तीन मुकदमे दर्ज हैं। वर्तमान मामले की जांच शुरू कर दी गई है, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गोण्डा जिले का 'करोड़पति बाबू' ...

» तनखाह क्लर्क की, टाट नवाबी! सात मकान, नौ गाड़ियां, पांच नौकर और दुबई में शाही टाट

» बेसिक शिक्षा विभाग के एक लिपिक की कहानी, जो भ्रष्टाचार की पाठशाला बन गया है

» विधायक के पत्र के बाद मचा हड़कम्प, अनूप सिंह इससे पहले कर चुके हैं शिकायत

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या/गोण्डा। वह एक साधारण सरकारी क्लर्क है कम से कम पदनाम से तो यही प्रतीत होता है। लेकिन जब उसकी संपत्ति की परतें खुलती हैं, तो लगता है जैसे किसी अरबपति कारोबारी की कहानी सुन रहे हों। अयोध्या बेसिक शिक्षा विभाग में वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में तैनात यह लिपिक, वर्षों से जिले में वेतन वितरण जैसे जिम्मेदार कार्य की आड़ में भ्रष्टाचार की ऐसी किताब लिखता रहा, जिसे पढ़कर ईमानदारी भी शरमा जाए।

तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पांडेय द्वारा मुख्यमंत्री को की गई शिकायत में आरोप है कि यह लिपिक न केवल आय से कई गुना अधिक संपत्ति का मालिक है, बल्कि उसने परिवारजनों को भी इस गोरखधंधे में शामिल कर रखा है। करोड़ों की चल-अचल संपत्तियों, फर्जी नियुक्तियों और सैलरी घोटाले की परत-दर-परत खुलती यह कहानी सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि सत्ता, सिस्टम और संवैधानिक मर्यादाओं की बेहूदा खिल्ली का जीवंत उदाहरण है।

सात मकान, नौ गाड़ियां और पांच नौकर!

शिकायत में दावा किया गया है कि लिपिक के



पास गोडा और लखनऊ में कुल 7 मकान, 9 लज्जरी गाड़ियां, 5 घरेलू नौकर, और करोड़ों की अवैध संपत्ति है। इतना ही नहीं, पत्नी और करीबियों के नाम पर आठ लज्जरी वाहन भी दर्ज हैं। क्लर्क की हैसियत में यह सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ? जवाब है तनखाह से नहीं, तिकड़मों से।

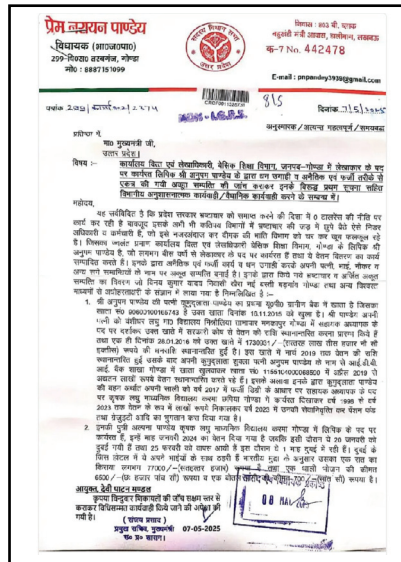
शिक्षक नियुक्ति घोटाला: साली, बेटे और पत्नी सब रिफ्ट में शामिल

विधायक की शिकायत के अनुसार लिपिक ने अपनी पत्नी के नाम से अलग-अलग बैंकों में खाते खुलवाए और एक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में फर्जी भुगतान कराया। यही नहीं, फर्जी डिग्री के आधार पर अपनी साली को शिक्षक नियुक्त कर लाखों रुपये की सैलरी दिलवाई गई। सबसे चौंकाने वाला मामला उनकी बेटे का है, जो जनवरी 2024 में दुबई गई और फरवरी के अंत में लौटी, लेकिन उसके नाम पर पूरा वेतन जारी कर दिया गया, जबकि किसी भी सक्षम अधिकारी से छुट्टी की अनुमति तक नहीं ली गई थी।

दुबई में शाही टाट- एक रात 77 हजार, एक थाली 6500

लिपिक की बेटे दुबई में जिस होटल में ठहरी, उसका एक रात का किराया 77,000, भोजन 6500 प्रति थाली, और एक बोतल पानी 700 बताई गई है। ये खर्च उस आदमी के खाते में दर्ज हो रहे हैं, जिसकी मासिक तनखाह मुश्किल से 40-50 हजार के बीच है।

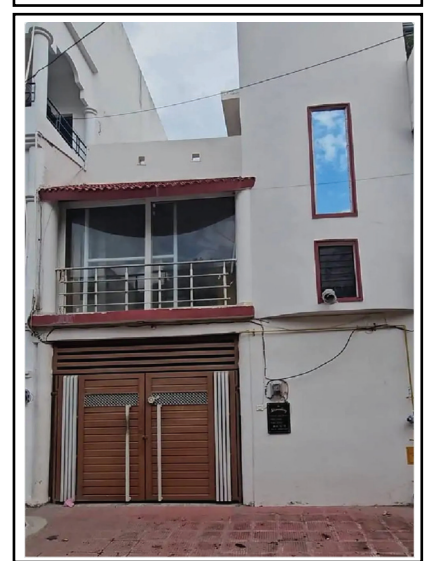
भाईयों के नाम पर भी चल रहा प्रॉपर्टी का खेल



विधायक का आरोप है कि लिपिक ने अपने भाईयों के नाम पर भी अवैध संपत्तियां खड़ी कर रखी हैं, जिससे ये साबित होता है कि पूरा परिवार एक सुनियोजित भ्रष्टाचार नेटवर्क की तरह काम कर रहा है। घर में नौकरों की फौज है, बैंक खातों में सदिग्ध लेन-देन की भरमार और विभागीय फाइलों में गड़बड़झाल।

मामला पहुंचा मुख्यमंत्री कार्यालय, जांच शुरू

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने देवीपाटन मंडल के आयुक्त को जांच का



आदेश भेजा है। मंडलायुक्त शशिभूषण लाल सुशील ने पुष्टि की है कि उन्हें पत्र प्राप्त हुआ है और फ़रकरण की गहन जांच कराई जा रही है। विधायक ने सीधे मांग की है कि इस पूरे घोटाले में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए। हालांकि कहा यह भी जा रहा कि विधायक मैनेज हो गए हैं लेकिन विधायक ने इस बात से साफ इंकार कर दिया है।

सोशल ऑडिट की आड़ में चल रहा वसूली का खेल!

» अयोध्या के स्कूलों में नकली पारदर्शिता की असली तस्वीर

इंटरनल यूनिवर्सिटी के छात्रों की आडिट टीम ने की 1100 रुपये की वसूली

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार अब किसी दफ्तर या ट्रांसफर पोस्टिंग तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब इसकी जड़ें बच्चों की पाठशाला तक पहुंच गई हैं। सोशल

ऑडिट जैसी पारदर्शी प्रक्रिया को भी कैसे रस्म अदायगी में बदला जा रहा है, इसका एक ताजा उदाहरण जनपद अयोध्या के रुदौली क्षेत्र से सामने आया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बेसिक शिक्षा विभाग के आदेशानुसार जनपद के परिषदीय विद्यालयों में लखनऊ की इंटरनल यूनिवर्सिटी से आए कुछ छात्रों द्वारा सोशल ऑडिट की जानी थी। आदेश में स्पष्ट था कि निर्धारित तिथियों पर छात्रों को स्कूलों में जाकर आडिट करनी थी, और स्कूल प्रशासन को उन्हें सहयोग देना था। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। कंपोजिट विद्यालय सरायनासिर, रुदौली के प्रभारी



शिकायतकर्ता बलबीर सिंह

प्रधानाध्यापक बलबीर सिंह ने एक पत्र के माध्यम से इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। बलबीर सिंह के अनुसार, निर्धारित तिथियों पर न तो कोई छात्र विद्यालय आए, और न ही किसी आडिट

स्वराज इंडिया का सवाल यह है

- व्या बेसिक शिक्षा विभाग ने इन तथाकथित छात्रों की पृष्ठभूमि की जांच की थी?
- व्या विभाग ने सोशल आडिट के लिए किसी गाइडलाइन का पालन किया?
- व्या वाकई यह छात्र अधिकृत थे या फर्जीवाड़े का हिस्सा?

की प्रक्रिया हुई। सप्ताह भर बाद जब आडिटर कहे जाने वाले छात्र स्कूल पहुंचे, तो उन्होंने सोशल ऑडिट की महज औपचारिकता निभाई, और चाय-पानी के नाम पर 1100 रुपये की मांग करने लगे जब प्रधानाध्यापक ने इस अवैध

वसूली का विरोध किया तो उन्हें अनुपस्थिति दर्ज कराने और नकारात्मक रिपोर्ट देने की धमकी दी गई। बलबीर सिंह ने कहा कि यदि यही सोशल आडिट है, तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार की नई शकल है।

प्रशासन चुप, सिस्टम मूक

सबसे हैरानी की बात यह है कि इस प्रकार की घटनाओं के बावजूद विभागीय अधिकारी मौन हैं। सोशल आडिट जैसी प्रक्रिया का उद्देश्य था कि विद्यालयों की कार्यप्रणाली को निष्पक्ष रूप से परखा जाए, लेकिन अगर यह ही प्रक्रिया धमकी और वसूली में बदल जाए तो सुधार की उम्मीद बेमानी हो जाती है।

अमेरिका का आतंक पर डबल स्टैंडर्ड!

टीआरएफ को बैन करने में लगे छह साल पाक का जित्त तक नहीं

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो/एजेंसी

नई दिल्ली। अमेरिका ने द रेसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। यह लश्कर-ए-तैयबा का एक फ्रंट है। इस कार्रवाई पर कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे अमेरिका को यह फैसला लेने में छह साल क्यों लगे, जबकि उसके पास टीआरएफ की गतिविधियों की खुफिया जानकारी थी। अमेरिका ने अपने बयान में पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया, जबकि लश्कर और टीआरएफ दोनों के लिए पाकिस्तान जन्म जैसा है।

अमेरिका ने उस टीआरएफ यानी 'दि रेजिस्टेंस फ्रंट' को आतंकी संगठन घोषित किया है जिसने पहलगांम में आतंकी हमला किया था। यह एक बड़ा घटनाक्रम रहा क्योंकि मौजूदा समय में अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इसके बावजूद भारत, अमेरिका से टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करवाने में सफल रहा है। पहलगांम हमले में 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का एक फ्रंट यानी अगला चेहरा है जिसने भारत पर कई हमले किए हैं।

भारत में बन रहा रामा कवच से लैस अभेद्य ड्रोन

अमेरिका, रूस, चीन ही अब तक बना पाए स्टेल्थ ड्रोन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो/एजेंसी

नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने न केवल पाकिस्तान को चारो खाने चित्त किया बल्कि अपने हवाई आक्रमण व रक्षा कवच का लोहा भी दुनिया भर में मनवाया। जल्द ही विश्व भारत की एक और हवाई ताकत से रूबरू होगा। भारत दुनिया में पहली बार ड्रोन स्टेल्थ ड्रोन बनाने वाला है जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है रामा कवच। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही दुनिया भारत की रक्षा प्रणाली की सामर्थ्य का लोहा मान रही है। भारत अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए ड्रोन स्टेल्थ ड्रोन बनाने की तैयारी कर रहा है, जो दुश्मन के हार्डरेंज रडार और इन्फ्रारेड सिग्नल्स से तो बचेगा ही, साथ ही 1 सेकंड से भी कम समय में हमला करने में भी सक्षम होगा।

रामा कवच ड्रोन को बनाएगा अभेद्य : भारत में बन रहे इस ड्रोन की खासियत जो बात इसे सबसे अलग बनाएगी वह है इसमें लगने वाला 'रामा' कवच। यह खास स्वदेशी कोटिंग मैटेरियल है जो इन्फ्रारेड और रडार की पहचान को 97 प्रतिशत तक कम कर देता है। भारत पहला देश होगा जो ड्रोन

» दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम, सेकंड्स में हमला करने की क्षमता
» रामा कवच के कारण यह ड्रोन होगा ड्रोन स्टेल्थ



स्टेल्थ ड्रोन बनाने में सक्षम होगा। दरअसल अमेरिका, चीन और रूस के पास भी अब तक सिर्फ रडार से छिपने वाले स्टेल्थ ड्रोन मौजूद हैं।

ड्रोन बनाने वाली कंपनी : हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी वीरा डायनामिक्स और बिनफोर्ड रिसर्च लैब

रक्षा मंत्रालय की मदद से इसे तैयार कर रही हैं। जो कंपनी के सीईओ साई तेजा ने बताया कि रामा यानी रडार अब्सॉर्प्शन एंड मल्टीस्पेक्ट्रल अडैप्टिव खास मैटेरियल है जो दुश्मन के रडार और इन्फ्रारेड सिग्नल से पूरी तरह छिप सकता है।

भारतीय सेना को कब तक मिलेगा ?

इसे एक साल में तैयार किया गया है और हर हफ्ते दो टेस्ट कर इसकी सटीकता भी परखी गई है। इसे 2025 के आखिरी तक रामा के साथ ड्रोन नौसेना को सौंपा जा सकता है। इसके लिए बातचीत चल रही है।

सेना को फायदा

इस ड्रोन से फायदा यह होगा कि जब 100 हमलावर ड्रोन भेजे जाते हैं तो मात्र 25 से 30 ही लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जबकि ये ड्रोन 80 से 85 लक्ष्य को भेद सकते हैं। इसका वजन 100 किलो है और 50 किलो तक का पेलोड लेकर जा सकता है।

जानिए रामा मैटेरियल

यह नैनोटेक आधारित स्टेल्थ कोटिंग है जो रडार और इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रम में विजिबिलिटी को कम करती है। इसे रैप करके या पेंट के माध्यम से ड्रोन पर लगाया जाता है। यह कार्बन पदार्थों का मिश्रण है जो रडार वेव्स को अब्सॉर्ब कर लेता है और एनर्जी से निकलने वाली हीट को खत्म कर देता है। इसकी वजह से थर्मल इंडीकेटर 1.5 सेल्सियस प्रति सेकंड कम हो जाता है। दरअसल जंग के समय दुश्मन सबसे पहले ड्रोन को ही पकड़ते हैं फिर इन्फ्रारेड से निशाना लगा नीचे गिरा देते हैं। रामा कवच ड्रोन को इन दोनों से बचाएगा। इसी कारण इसे ड्रोन स्टेल्थ ड्रोन कहा जा रहा है।

मानसून सत्र

यह घोषणा राज्य विधानसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन की गई

महाराष्ट्र सरकार ने इस्लामपुर का नाम बदल ईश्वरपुर किया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि सांगली जिले के इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है। यह घोषणा राज्य विधानसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन की गई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छान भुजबल ने विधानसभा को बताया कि गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कैबिनेट के इस फैसले को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजेगी।

यह कदम हिंदूवादी संगठन शिव प्रतिष्ठान द्वारा सांगली कलेक्ट्रेट को एक ज्ञापन भेजकर इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने की मांग के बाद

1986 से चली आ रही है बदलने की मांग, सरकार इस फैसले को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजेगी



राज्य सरकार बलपूर्वक या धोखे से किए जा रहे धर्मांतरण से संबंधित मामलों से निपटने के लिए कड़े प्रावधान लाने पर विचार कर रही है

उठाया गया है। शिव प्रतिष्ठान का नेतृत्व संभाजी भिडे कर रहे हैं, जिनके समर्थकों ने कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी

नहीं हो जाती, वे चैन से नहीं बैठेंगे। इस्लामपुर के एक शिवसेना नेता ने बताया कि नाम बदलने की मांग 1986 से चली

आ रही है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर हिंदू, बौद्ध और सिख

धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म के व्यक्ति ने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हासिल किया है, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा।

फडणवीस ने विधान परिषद में कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने सरकारी नौकरियों जैसे आरक्षण का लाभ हासिल किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके चुनाव जीता है, तो उसका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार बलपूर्वक या धोखे से किए जा रहे धर्मांतरण से संबंधित मामलों से निपटने के लिए कड़े प्रावधान लाने पर विचार कर रही है और इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।